

आदेश की क्रम संख्या
एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

2

30-01-2012

न्यायालय, समाहर्ता पूर्णियाँ**नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं०-14/2005**कारे लाल यादव, पिता-श्री सुखदेव यादव
सा०-परोरा, थाना-के०नगर, जिला-पूर्णियाँ

---आवेदक

बनाम

1. गिरिजा नन्द यादव, पिता-श्री सुखदेव यादव
सा०-परोरा, थाना-के०नगर, जिला-पूर्णियाँ
2. राज्य
3. भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर
4. अंचल अधिकारी, के०नगर

---विपक्षी

आवेदक भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं० 7/03 में दिनांक-28.01.05 को पारित आदेश के विरुद्ध यह वाद प्रारंभ किया है। आवेदक को मौजा परोरा, थाना नं० 126, 127, 128 खाता सं० 116 खेसरा सं० 2298 रकवा 2.02 एकड़ जमीन पर बटाईदारी वाद सं० 66/88-89 में पारित आदेश द्वारा रैयत घोषित किया गया था। पुनः आवेदक ने अंचल पदाधिकारी के०नगर के न्यायालय में धारा 48 D अन्तर्गत वाद 01/01 दायर किया और अंचल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 25.02.02 को आवेदक को रैयत घोषित किया गया। विपक्षी सं० 1 आवेदक का भाई है और उपरोक्त प्रश्नगत जमीन पर अपने हिस्सा की जमीन का नामान्तरण हेतु अंचल पदाधिकारी के न्यायालय में आवेदन दिया। इस नामान्तरण वाद सं० 14/03-04 में अंचल पदाधिकारी द्वारा स्थल जांच के आधार पर विपक्षी के नामान्तरण वाद को खारिज कर दिया। तदुपरांत विपक्षी सं० 1 भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं० 7/03 दायर किया। निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किया गया एवं अंचल पदाधिकारी द्वारा नामान्तरण वाद में पारित आदेश को रद्द किया गया। प्रश्नगत जमीन आवेदक के बटाईदारी वाद द्वारा प्राप्त की गई थी और आवेदक के ही दखल में है। फलस्वरूप निम्न न्यायालय द्वारा नियम के विपरीत आदेश पारित किया गया। अतः आवेदक इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि वाद की सुनवाई कर न्याय प्रदान करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक के द्वारा प्रारंभ किया गया यह वाद किसी भी दृष्टिकोण से निर्वहन योग्य नहीं है। आवेदक ने अपने वाद पत्र में वास्तविक तथ्यों को छिपाया है। जबकि निम्न न्यायालय में अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन करते हुए आदेश पारित किया गया है। अतः विपक्षी इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किए गए इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 19.07.2010 को सुनवाई की गयी। आवेदक अनुपस्थित रहे। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा आवेदक के बराबर अनुपस्थित रहने के कारण वाद को खारिज करने की मांग किया गया। दिनांक 16.06.2010 को अंतिम मौका देते हुए न्यायालय में उपस्थित रहने का अंतिम मौका दिया गया। इसके बावजूद भी आवेदक न्यायालय में उपस्थित रहना उचित नहीं समझा।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि प्रश्नगत जमीन उनके शांति

आदेश पर न
मौका देते हुए
अंतिम मौका
दिया गया
3

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या
एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कॉपी के म
तारीख
3

1

2

पूर्ण दखल-कब्जा में है। इस कारण से ही उनके पक्ष में निम्न न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया। आवेदक के द्वारा जान बुझकर वाद की निष्पादन में विलम्ब करने का मंशा है, इस कारण से उपस्थित होने हेतु उनको कोई रूचि नहीं है।

पुनः दिनांक 27.01.2012 को सुनवाई हेतु रखी गयी।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई के बाद स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता है। आवेदक के द्वारा भी इस वाद के निष्पादन में कोई रूचि नहीं लिया जा रहा है बल्कि निष्पादन में विलम्ब करने का मंशा भी स्पष्ट प्रतीत होता है इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता, पूर्णियाँ

समाहर्ता, पूर्णियाँ